सब्सिडी हटाएँ मगर धीरे धीरे

जे.डी. अग्रवाल

निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंस

सुविख्यात फाइनेंस विशेषज्ञ और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंस के निदेशक प्रोफेसर जे डी अग्रवाल कहते हैं कि विभिन्न वर्गों को सब्सिडी देने का उद्देश्य उन्हें शुरूआती दौर में सहारा देना होता है। जनकल्याण के नजरिए से लोकतांत्रिक सरकार का यह कर्तव्य भी होता है। मगर सब्सिडी को हमेशा जारी नहीं रखा जा सकता। उसे चरणबद्ध तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके हटाया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी वास्तव में हैं क्या?

राशन, उर्वरक और रसोई गैस जैसी चीजों को जनता को वास्तविक बाजार भाव से कम में उपलब्ध कराने के लिए सरकार अपने खजाने से जो नकद राशि खर्च करती है, वह प्रत्यक्ष सब्सिडी है जबकि पानी, बिजली, सड़क और उच्च शिक्षा आदि के विराट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने जो पूँजी लगाई है और जिसका जनता के विभिन्न वर्ग नाम मात्र के शुल्क चुकाकर उपभोग करते हैं वह अप्रत्यक्ष सब्सिडी की मद में आता है। मसलन अगर कोई निजी कंपनी जल आपूर्ति तंत्र खड़ा करती तो पानी की दरें मौजूदा दरों से कई गुना ज्यादा होती। मगर सरकार अपनी पूरी लागत का खर्च जनता से नहीं वसूलती। गाँवों में बिजली की आपूर्ति के लिए सरकार ने अरबों रूपए खर्च किए मगर किसानों से बिजली की रियायती दरें ही वसूली जाती हैं। यह अप्रत्यक्ष सब्सिडी की मिसाल हैं।

सब्सिडी हटाने का आर्थिक तर्क क्या है?

अर्थशास्त्र लगातार खैरात देते रहने की हिमायत नहीं करता, सब्सिडी, विभिन्न जनवर्गों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दी जाती है, हमेशा के लिए बैसाखी बनने के लिए नहीं। अंत में प्रत्येक आयवर्ग, प्रत्येक उद्योग को आत्मनिर्भर होना होता है। फिर सब्सिडी का लाभ अक्सर गलत वर्गों को मिलता है। मसलन उच्च शिक्षा में अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो सब्सिडी सरकार देती है, उसका फायदा बड़ी कंपनियों को मिलता है। उन्हें बिना कुछ ज्यादा खर्च किए प्रशिक्षित एक्जीक्यूटिव मिल जाते हैं। रसोई गैस को सब्सिडी से शहरी संपन्न उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है। यही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की चीजों के साथ भी हो रहा है।

राशन के भाव बढ़ाए जाने पर आपकी प्रतिक्रिया?

एक झटके में 30 प्रतिशत सब्सिडी कटौती को मैं सही नहीं मानता। पहले आप किसी वर्ग को सब्सिडी का आदी बना दें, फिर झटके से उसे वापस लें, यह सही तरीका नहीं है।

भारत की बड़ी आबादी गरीब है। सब्सिडियाँ हटने पर उसका क्या होगा।

गरीब और बहुत गरीब लोगों के लिए सब्सिडी देने की जरूरत कभी नहीं झुठलाई जा सकेगी। मगर हमेशा उन्हें सब्सिडी का मोहताज रखना भी ठीक नहीं।

प्रस्तुतिः संजय अभिज्ञान